भारत सरकार
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
बायोटेक्नोलॉजी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3922

उत्तर देने की तारीख : 19 मार्च, 2021

मिशन नवाचार

3922. श्री राजेन्द्र धेड्या गावित:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री चन्द्र शेखर साहू:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ऊर्जा, जल, स्वास्थ्य और खगोल विज्ञान, जो कि दुनिया को जीने के लिए एक बेहतर और अधिक वैज्ञानिक स्थान बनाने के समक्ष वैश्विक चुनौतियां हैं, जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विश्व में एस एंड टी भागीदारी के प्रमुख सदस्य के रूप में उभरा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारत ने वैश्विक पहल 'मिशन नवाचार' शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान मिशन नवाचार के तहत आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने विभिन्न भारतीय और विदेशी संस्थानों और उद्योगों को शामिल करने वाले स्मार्ट ग्रिड के तहत आरएंडडी परियोजना को निधि आवंटित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(क) क्या कोविड-19 महामारी ने इस उत्पन्न संकट से निपटने में एक अग्रणी देश के रूप में भारत की स्थिति स्थापित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण; विज्ञान और प्रौद्योगिकी; तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री
(डॉ. हर्ष वर्धन)

(क)जी हां, भारत ने प्रमुख देशों के साथ भागीदारी स्थापित की है और जैवप्रौद्योगिकी एवं संबद्ध विषयों के क्षेत्रों जैसे ऊर्जा, जल, स्वास्थ्य जैसी वैश्विक चुनौतियों में

ज्ञान सृजन और नवाचारों के माध्यम से मुख्य भूमिका निभा रहा है। इसलिए, भारत गंभीर क्षेत्रों में वैश्विक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी साझेदारियों में एक मुख्य प्रवर्तक के रूप में उभरा है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, बायोटेक्नोलॉजी विभाग और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा मुख्य मिशन शुरू किए गए हैं।

(ख) जी हां, मिशन नवाचार (एमआई) 24 देशों और यूरोपियन संघ की एक वैश्विक पहल है और 30 नवम्बर, 2015 को सीओपी 21 में पेरिस समझौते के दौरान आरंभ की गई थी। यह कार्यक्रम स्वच्छ ऊर्जा नवाचारों को बढ़ाने के लिए स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान, विकास और प्रदर्शन (अनुसंधान विकास और प्रदर्शन) पहलों पर केंद्रित है।

बायोटेक्नोलॉजी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और अन्य संरेखित मंत्रालयों के साथ निकट सहयोग में स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान, विकास और प्रदर्शन में राष्ट्रीय प्रयासों के समन्वय और विभिन्न कार्यों के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। भारत आठ नवाचार चुनौतियों में भागीदारी करके और तीन चुनौतियों (स्मार्ट ग्रिड, विद्युत तक ऑफ ग्रिड पहुंच और वहनीय जैव ईंधनों) का सह-नेतृत्व करके वैश्विक स्तर पर एमआई कार्यकलापों में मुख्य भूमिका निभा रहा है। भारत मिशन नवाचार संचालन समिति का सदस्य है और कनाडा के साथ विश्लेषण और संयुक्त अनुसंधान उप-समूह का सह-नेतृत्व करता है। भारत ने सामाजिक हित के लिए अत्यधिक प्रभावपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा समाधान प्रदान करने हेतु स्टार्ट-अप को समर्थन देने के लिए स्वच्छ ऊर्जा अंतर्राष्ट्रीय इन्क्यूबेशन केंद्र की स्थापना की है।

(ग) मिशन नवाचार भारतीय कार्यकलापों के लिए पिछले तीन वर्षों का समेकित बजट-

धनराशि (रुपए में)		
वर्ष	कुल स्वीकृत	कुल जारी
वित्त वर्ष 2017-18	13,39,16,108	74,98,100
वित्त वर्ष 2018-19	68,52,54,134	41,24,49,842
वित्त वर्ष 2019-20	44,63,83,106	29,63,76,145
कुल	126,55,53,348	71,63,24,087

(घ) जी हां, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग कनाडा, नार्वे, यूके, जर्मनी, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इटली के सहभागी संस्थानों के साथ सहयोग से विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों, विश्वविद्यालयों, आईआईटी में स्मार्ट ग्रिड पर अनुसंधान और विकास परियोजनाओं का समर्थन कर रहा है। सरकार ने स्मार्ट ग्रिड पर भारत-स्वीडन सहयोगी औद्योगिक अनुसंधान और विकास कार्यक्रम 2020 के लिए 18 करोड़ रुपए की धनराशि की प्रतिबद्धता की है। स्मार्ट ग्रिड पर अनुसंधान और विकास के लिए कुल 9 परियोजनाओं का समर्थन किया गया है।

(ड.) जी हां, भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए मुख्य कदम उठाए हैं। इस महामारी ने भारत को वैश्विक हित के लिए स्वदेशी जैव विनिर्माण क्षमताओं को तैयार करने का एक अनूठा अवसर प्रदान किया है। कोविड-19 और नैदानिक परीक्षणों के लिए 15 वैक्सीन कैंडीडेट्स को समर्थन दिया जा रहा है। दो वैक्सीनों ने पहले ही आपातकालीन उपयोग अधिकार (ईयूए) प्राप्त कर लिया है। भारत सरकार की 'वैक्सीन मैत्री' पहल के माध्यम से, पूरे विश्व में विभिन्न सहभागी राष्ट्रों के लिए कोविड-19 वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए भारत की विकट वैक्सीन विनिर्माण क्षमता का लाभ उठाया जा रहा है। नैदानिक परीक्षणों को बढ़ाने के लिए साझेदारी (पीएसीटी) के तहत, बायोटेक्नोलॉजी विभाग (डीबीटी) पड़ोसी देशों में वैक्सीन विकास कार्यकलापों को बढ़ाने और पड़ोसी देशों में नैदानिक परीक्षण को मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन के लिए विदेश मंत्रालय के साथ निकट रूप से कार्य कर रहा है। स्वदेशी नैदानिक विकास की दिशा में भी एक मुख्य प्रयास किया गया है।

*****